<u>निर्देश संख्या 58</u>

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में,

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

17वाँ तल, जवाहर व्यापार भवन,
एस. टी. सी. बिल्डिंग, नई दिल्ली – 110016

फा. सं. 110018 /01 /2021/सी. ए. क्यू एम./ 6806-6813 दिनांक: 22.02.2022

विषय: : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन अयोग अधिनियम 2021 की धारा 12 के तेहत दिल्ली

जबकि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सरकार भारत के, आयोग की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए अधिनियम 2O2I, ने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन किया है राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र (बाद में आयोग के रूप में संदर्भित);

जबकि, अधिनियम की धारा 12(1) के तहत, आयोग के पास अधिकार है ऐसे सभी उपाय, निर्देश जारी करना, आदि, जैसा कि यह आवश्यक या समीचीन समझता है राष्ट्रीय में हवा की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार करने का उद्देश्य राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र; जबकि, अधिनियम की धारा 12 (21 (v) के तहत आयोग के पास अधिकार हैं: किसी भी उद्योग, संचालन या प्रक्रिया को चलाने वाले क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगाना क्षेत्र में वायु गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है;

जबकि, अधिनियम की धारा L2 (2) (xi), आयोग को जारी करने का अधिकार देती है

किसी व्यक्ति, अधिकारी, या किसी प्राधिकारी और ऐसे व्यक्ति को लिखित में निर्देश,

अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे; जबकि, आयोग ने बार-बार हवा से संबंधित मामले को उठाया है हर5राणा, राजस्थान, पंजाब की राज्य सरकारों के साथ एनसीआर में प्रदूषण, उत्तर प्रदेश और एनसीटी दिल्ली सरकार और विभिन्न संगठन

केंद्र और राज्य सरकारों / जीएनसीटीडी से संबंधित है और जारी किया है विभिन्न दिशा-निर्देश, आदेश और प्रभावी करने के लिए विशिष्ट निर्णय भी लिया है एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के उपायों का समय-समय पर कार्यान्वयन समय; जबकि, आयोग इस बात पर प्रकाश डालता रहा है कि अन्य बातों के अलावा, डीजल जेनरेटर (डीजी) सेटों का अनियंत्रित उपयोग के लिए एक प्रमुख योगदान कारक है क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में गिरावट; जबकि, GRAP के अनुरूप एनसीआर में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के मद्देनजर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नवंबर, 2OL7, आपातकालीन उद्देश्यों को छोड़कर, डीजी सेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है एनसीआर में जब भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता "बहुत खराब" श्रेणी में आती है (एक्यूआर>300); जबकि, बड़ी संख्या में उद्योग, संघ, संघ और व्यक्तिगत संस्थाओं ने आयोग के समक्ष प्रतिनिधित्व किया है कि केवल नियमित बिजली आपूर्ति में रुकावट, ऐसी इकाइयों को सहारा लेने के लिए मजबूर किया जाता है डीजी सेट संचालन; जबकि, उक्त इकाइयों ने आगे निवेदन किया है कि कुछ निरंतर औद्योगिक प्रक्रियाएँ और उत्पादन व्यवस्थाएँ भारत में निर्बाध बिजली की माँग करती हैं इन-प्रोसेस इन्वेंट्री और अर्ध-तैयार उत्पादों को उबारने में रुचि और कई मामलों में भी विभिन्न सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी प्रणालियों के संचालन के लिए /

उपकरण; जबकि, कुछ संस्थाओं ने यह भी प्रतिनिधित्व किया है कि वे इसमें लगे हुए हैं दूरसंचार और डेटा सेवाएं जिनके लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है और इस प्रकार डीजी सेटों पर अत्यधिक निर्भरता हो जाती है;

जबकि, वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और कम करना बहुत महत्वपूर्ण है क्षेत्र में विशेष रूप से सर्दियों के महीनों के दौरान डीजी सेट द्वारा; जबकि, उपरोक्त विचारों के मद्देनजर, आयोग ने अपने निर्देश संख्या" 54-57 दिनांक 09.02.2022 ने सीमित उपयोग के लिए सख्त शर्त जारी की ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के दौरान डीजी सेट योजना (जीआरएपी);

जबकि, निदेश 54 - 57 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संदर्भित ऊपर से, राष्ट्रीय में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना अनिवार्य है राजधानी क्षेत्र; अब, इसलिए, डीजी . से वायु प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए सेट और डीजल जेनरेटर सेटों के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए आयोग के प्रयोग में वायु गुणवत्ता आयोग की धारा 12 के तहत निहित शक्तियां एनसीआर और आस-पास के क्षेत्रों में प्रबंधन अधिनियम 2021, इसके द्वारा डिस्कॉम्स को निर्देश देता है

पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्यरत:-

(एल बिजली की मांग का व्यापक आकलन करें और पर्याप्त पहल करें सुनिश्चित करने की दिशा में पर्याप्त रूप से पहले से उपाय और योजनाएँ निर्बाध विद्युत आपूर्ति; तथा विशेष रूप से एनसीआर में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें अक्टूबर - फरवरी के बीच की अवधि जब में वायु गुणवत्ता सूचकांक क्षेत्र आम तौर पर गरीब । बहुत कमजोर । गंभीर श्रेणी में रहता है;इसके अलावा, यह निर्देश दिया जाता है कि एनसीटी दिल्ली और एनसीआर राज्य की सरकार सरकारें संबंधित शक्ति के साथ मामले को प्रभावी ढंग से उठाएगी वितरण कंपनियों को विशेष रूप से के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अक्टूबर से फरवरी का महीना। इन निदेशों का पालन न करने को के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा एनसीआर और आसपास के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के प्रावधान क्षेत्र अधिनियम 2021 और बिजली वितरण के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है संबंधित कानूनों के साथ-साथ अधिरोपण के तहत संबंधित कंपनियां / अधिकारी और पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लगाना।

हस्ता०

(**अरविंद नौटियाल)**
सदस्य सचिव
दूरभाष नं.: 011-23701197
E-mail: arvind.nautiyal@gov.in

प्रति:

1. सीईओ, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड।

2. सीईओ, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड।

3. सीईओ, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड।

4. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर परिषद

5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, विद्युत, एनसीटी सरकार, दिल्ली

(**अरविंद नौटियाल)**
सदस्य सचिव